

भाग-III**हरियाणा सरकार****न्याय प्रशासन विभाग****अधिसूचना****दिनांक 22 फरवरी, 2019**

संख्या का०आ० 13/के०आ० 5/1908/धा० 2/2019.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5), की धारा 2 के खण्ड (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त खण्ड द्वारा पहले से नियुक्त हरियाणा राज्य के सभी सरकारी प्लीडरों को हरियाणा राज्य में अपनी—अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 4 तथा आदेश XXXIII के नियम 6 द्वारा स्पष्ट रूप से अधिरोपित सभी कृत्यों की पालना करने के लिए सशक्त करते हैं।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 22nd February, 2019

No. S.O. 13/C.A. 5/1908/S. 2/2019.— In exercise of the powers conferred by clause (7) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), the Governor of Haryana hereby empowers all the Government Pleaders of the State of Haryana as already appointed by the said clause to perform all the functions expressly imposed by the rule 4 of order XXVII, and rule 6 of order XXXIII of the First Schedule of the said code for whole of the State of Haryana in their respective jurisdiction.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

8540—C.S.—H.G.P., Pkl.